248 करोड़ खर्च, लेकिन स्मार्ट की जगह बदसूरत सड़कें

वीरेन्द्र वर्मा

इंदौर. प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना का इंदौर में पलीता लग गया. केंद्र सरकार के एक हजार करोड़ से शहर को विशेष पैकेज से आकर्षक बनाना था, लेकिन खूबसूरत की जगह बदसूरत ज्यादा नजर आ रहा है. स्मार्ट सिटी के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान में 248 करोड़ में 14.3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी , लेकिन इसका सबूत है कि स्मार्ट सिटी एरिया में एक स्मार्ट सड़क को चेंबर वाली गली के नाम से पहचाना जाता है! इतना ही नहीं उक्त चेंबर वाली गली के क्षेत्र का वास्तविक नाम ही बदल दिया, जो राजमोहल्ला था.

स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र को एबीडी के लिए चुना गया था. इसमें राजबाड़ा के आसपास का इलाका बड़ा गणपति, महूनाका और राजमोहल्ला, जयरामपुर कॉलोनी और मच्छी बाजार तक सीमा तय की गई थी. उक्त क्षेत्र में शहर के सभी प्रमुख बाजार हैं, जिसमें सराफा, कपड़ा मार्केट, बर्तन, रेडीमेड, किराना, सब्जी मंडी जैसे थोक एवं खेरची व्यापारिक केंद्र शामिल है. शहर की जनता को स्मार्ट सिटी के तहत लंदन, पेरिस जैसी सड़क और व्यापार क्षेत्र विकसित करने के सब्ज़ बाग दिखाए गए. इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए सिर्फ स्मार्ट सिटी के सेटअप पर ही खर्चा कर दिए गए. स्मार्ट सिटी के तहत राजबाड़ा के आसपास सहित कुल 14.3 किलोमीटर लंबी सड़कों को निर्माण किया गया है. उक्त 14.3 किलोमीटर सीमेट की सड़कों पर करोड़ 248 खर्च किए गए है, जिसमें एक कंपनी के 5 करोड़ रुपए छोड़कर बाकी का भुगतान तक निर्माण एजेंसियों को कर दिया गया है.

इसमें स्मार्ट सड़क का नाम चेंबर वाली गली जो राजमोहल्ला में स्थित है, बनाई है. चेंबर वाली गली इसलिए कि गली में करीब 75 से 100 सौ चेंबर है. यही नहीं सड़क निर्माण का कई जगह काम अधूरा है, लेकिन निर्माण का भुगतान पूरा कर दिया गया है. स्मार्ट सिटी ने तीर्थ गोपीकॉन कंपनी का 5 करोड़ रुपए भुगतान रोका है, वो भी फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आने के बाद. उक्त कंपनी ने ही बड़ा गणपति से किशनपुरा तक स्मार्ट सड़क का निर्माण किया, जिस पर पिछले महीने गौराकुंड चौराहे पर पानी लाइन टेस्टिंग में सड़क के नीचे से पानी बाहर आ गया था.

इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को खूबसूरत बनाने की जगह बदसूरत और बदहाल बना दिया गया. सिर्फ एक काम जरूर किया कि शहर को डामर की जगह सीमेंट कांक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया. हालत यह है कि न सांस्कृतिक और न ही शहर की पहचान के अनुरूप विकास हुआ. इस सबसे बढ़कर यह कि निगम की न राजस्व आय बढ़ी और न ही रोजगार पैदा हो सके. कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी में अधिकारियों ने चांदी काटी और शहर एवं जनता के हिस्से कुछ भी नहीं आया.

40 करोड़ की जगह कर दिए 2 सौ करोड़ खर्च

ऐसी चर्चा है कि स्मार्ट सिटी के सेटअप पर करीब 200 सौ करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें ऑफिस, वाहन, कंप्यूटर आदि शामिल हैं. केंद्र सरकार के नियम थे कि कुल राशि का 4 प्रतिशत सिस्टम डेवलप यानि ऑफ़िस, वाहन और अन्य संसाधन पर खर्च कर सकते हैं. इंदौर में 4 प्रतिशत राशि यानि 40 करोड़ की जगह 200 सौ करोड़ मतलब 20 प्रतिशत राशि संसाधन और ऑफिस डेवलपमेंट पर खर्चा करने की जानकारी मिली है. कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों ने शहर के विकास की बजाय अपनी सुख सुविधाओं पर 16 प्रतिशत राशि ज्यादा खर्चा किया. शहर अभी भी बदसूरत और बदहाल ही है.

प्रधानमंत्री ने शुरू की थी स्मार्ट सिटी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शहरों को क्षेत्र एवं संस्कृति के हिसाब से विकसित करने हेतु स्मार्ट सिटी योजना शुरू की थी. इसके पहले चरण में 7 शहरों को शामिल किया गया था. दूसरे चरण में 23 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर भी शामिल था. स्मार्ट सिटी योजना में विशेष पैकेज के तहत 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे. एक हज़ार करोड़ रुपए से शहरों को अपनी विरासत और संस्कृति के हिसाब से क्षेत्र विकसित करना थे, जिससे रोजगार और राजस्व दोनों में इजाफा हो, लेकिन इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत योजना अनुरूप कुछ नहीं हो सका. केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना बंद कर दी.

अधिकारियों ने मनमाना बोर्ड बनाकर शहर को चूना लगाया :

नगर निगम जनकार्य प्रभारी राजेन्द्र राठौर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत बहुत घटिया काम हुआ है. शहर के गांधी हॉल, नेहरू पार्क ओर सड़कों का इतना घटिया काम हुआ ओर अधिकारियों ने 1 हजार करोड़ का चुना लगाया है. अधिकारियों ने आपस में ही मिलकर बोर्ड बना लिया. किसी से कोई अनुमति नहीं ली. शहर में सड़कों का इतना घटिया काम हुआ है कि फिर से बनाना पड़ेगी. हमने सरकार और प्रधानमंत्री को 1 हजार करोड़ रुपए के काम की जांच करने का पत्र लिखा हैं. हम लोग चाहते हैं कि मामले में विशेष आयोग बनाकर स्मार्ट सिटी के कामों की जांच हो क्योंकि स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य में किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। महापौर तक को जानकारी नहीं दी गई. हम एक हजार करोड़ का चूना लगाने के मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

विस्तृत जानकारी लूंगा : अर्थ जैन

स्मार्ट सिटी सीईओ आईएएस अर्थ जैन ने बताया कि मेरे समय का मामला नहीं है. स्मार्ट सिटी का सड़कों में क्या हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है. मैं विस्तृत जानकारी लेकर ही कुछ कह पाऊंगा.

इनका कहना है ...

सराफा व्यापारी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि पहले सड़क अच्छी थी. स्मार्ट सिटी में बनी सड़क से परेशानी बढ़ गई है. पानी भरा जाता है और आम जनता और व्यापारियों को स्मार्ट सिटी सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ. स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वैसा तो कुछ भी नजर नहीं आता है. परेशानी बढ़ गई है.

रहवासी आशीष दुबे ने कहा कि सड़क चौड़ी होने के अलावा कोई फायदा नहीं. स्मार्ट सिटी में राजमोहल्ला की गली में चेंबर ही चेंबर बने हैं. सड़क की जगह चेंबर नजर आते है. व्यापार और अन्य स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है.

एक नजर में

समारोह में प्रतिभाओं का किया सम्मान

इंदौर. भीमा नायक वनांचल सेवा संस्था और माँ नर्मदा फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में क्षेत्र की 350 विभिन्न प्रतिभाओं एवं 42 शासकीय विद्यालयों को सम्मानित किया गया. समारोह में मुख्य अतिथि विधायक डॉ. उषा ठाकुर, विधायक रहीं. वहीं विशिष्ट अतिथि राकेश परमार, अनुविभागीय अधिकारी महू तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सुमेश डाकवाले, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (महू) ने की. मुख्य वक्ता के रूप में रूपसिंह नागर, प्रांत संयोजक जनजाति विकास मंच, मालवा प्रांत उपस्थित रहे. कार्यक्रम में दीपा सारडा, डायरेक्टर श्रेया एग्रो, मानपुर (महू) तथा बलराम पाटीदार, डायरेक्टर ध्रुविका बिल्डकॉन, इंदौर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉ. पुंजालाल निनामा ने रखी. स्वागत उद्बोधन अजमेरसिंह भंवर एवं विशेष उद्बोधन हंसराज पटेल तथा सरदार मालवीय द्वारा दिया गया. विनोद पाटीदार और श्रद्धा सिसोदिया ने आभार माना.

समाजसेवा के लिए शिखा सम्मानित

इंदौर. शहर की जानी-मानी पॉडकास्टर, समाजसेवी और आंत्रप्रेन्योर शिखा काबरा को उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. यह सम्मान होटल शेरेटन ग्रैंड में प्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने प्रदान किया. य कृष्णा ने कहा कि महिलाओं का समाज के लिए काम करना एक प्रेरणादायी पहल है. इस दौरान कॉमेडियन राजीव ठाकुर भी मौजूद थे.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 8 अक्टूबर से

इंदौर. अमेजन.इन ने आज घोषणा की कि अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 8 अक्टूबर से शुरू होगा. जैसे ही भारत त्योहारी सीज़न के लिए तैयार हो रहा है, ग्राहक सबसे तेज़ डिलीवरी स्पीड के साथ शानदार कीमतों पर सबसे बड़े चयन की उम्मीद कर सकते हैं. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, घर की ज़रूरी चीज़ों और ग्रॉसरी सहित सभी लोकप्रिय श्रेणियों में डील्स उपलब्ध हैं. ग्राहकों को एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड तथा ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है. इस अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है. अमेज़न इंडिया के वीपी, सौरभ श्रीवास्तव ने कहा अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल देश के सबसे बड़े शॉपिंग उत्सव के लिए ग्राहकों, सेलर्स और ब्रांड्स को एक साथ लाकर भारतीय त्योहारों की भावना का जश्न मनाता है. इस साल, पूरे भारत के ग्राहक करोड़ों प्रोडक्ट्स पर साल की सबसे कम कीमतों, ब्लॉकबस्टर डील्स और रोमांचक नए लॉन्च की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम और वैल्यू प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े चयन की डिलीवरी मिनटों, घंटों, उसी दिन या अगले दिन की जाएगी.

मारुति सुजुकी ने ऑटो ग्रीन मिशन की शुरुआत की

नई दिल्ली, 18 सितंबर 2026- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (मारुति सुजुकी), स्वच्छ और हरित मोबिलिटी की अग्रणी कंपनी, ने लोकप्रिय स्विफ्ट डिज़ायर और बलेनो के ऑटोमैटिक एस-सीएनजी मॉडल पेश करते हुए 'ऑटो ग्रीन मिशन' की शुरुआत की है. यह नई रेंज, नए दौर के उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते. यह गाड़ियाँ ऑटोमैटिक ड्राइविंग की सुविधा के साथ बेहतरीन ईंधन दक्षता प्रदान करती है. इनमें से डिज़ायर ऑटोमैटिक एस-सीएनजी 36.47 किमी/किग्रा की ईंधन दक्षता के साथ अब भारत की सबसे अधिक ईंधन-कुशल सेडान बन गई है. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने नई ऑटोमैटिक एस-सीएनजी रेंज पेश करते हुए कहा मारुति सुजुकी ने हमेशा अपने ग्राहकों की बात सुनी है. भारत के शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और नई पीढ़ी के ग्राहक चाहते हैं कि उन्हें ऑटोमैटिक कार की सुविधा मिले, लेकिन ट्रैफिक में माइलेज और परफॉर्मेंस से समझौता न करना पड़े. ऑटो ग्रीन मिशन के तहत, हमारी नई ऑटोमैटिक एस-सीएनजी रेंज आज के ऐसे ही ग्राहकों के लिए बनी है, जो दोनों चीज़ें एक साथ चाहते हैं.

पूरे प्रदेश में होगा छात्रों की गूंज' कार्यक्रम, प्रदेश कांग्रेस ने रूपरेखा बनाना किया शुरू

नवभारत न्यूज़

इंदौर. इंदौर में 19 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं की भीड़ से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस अभियान को ले जाने की तैयारी कर रही है. कार्यक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस की जिला स्तर पर युवकों और उनके अभिभावकों से शिक्षा और अन्य समस्याओं पर चर्चा करने का व्यापक कार्यक्रम बनाने की योजना है.

इंदौर में भारत जोड़ो मैदान में 19 सितंबर को कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान में छात्रों के सैलाब ने कांग्रेस को आगे की रुपरेखा बनाने का रास्ता सुझा दिया है. मध्यप्रदेश कांग्रेस इस अभियान को प्रदेश के सभी जिलों तक ले जाने की तैयारी कर रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान इंदौर तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्रों, युवाओं और अभिभावकों के बीच पहुंचकर शिक्षा से जुड़े सवाल और उनकी समस्याएं सुनेंगे. उसके बाद छात्रों की गूंज अभियान से जोड़कर युवाओं से संवाद किया जाएगा. जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश और क्षेत्रीय नेता चर्चा करेंगे. साथ ही छात्रों की मांग और समस्याओं का प्रदेश और जिला स्तर पर समाधान करने हेतु आधुनिक और रोजगार मूलक शिक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी.

छात्रों ने तथ्यों के साथ सच का आईना दिखाया

छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रदेश, जिला और शहर कांग्रेस ने सभी का आभार जताया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर बता दिया कि उनके सवालों को अब दबाया नहीं जा सकता है. भाजपा की झूठ की गूंज का युवाओं ने सच की गूंज से जवाब दिया. प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा के हर झूठ पर राहुल गांधी और छात्रों ने तथ्यों के साथ सच का आईना दिखाया है. राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से युवाओं को अपनी मांगों और समस्याओं को सामने लाने का मंच दिया है. प्रेस से चर्चा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, दीपू यादव, निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट भाटिया, मोतीसिंह पटेल, राजेंद्र मालवीय, राजा चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया, प्रवक्ता अमित चौरसिया, प्रमोद द्विवेदी, संजय बाकलीवाल, इम्तियाज़ बेलिम ,लोकेश हार्डिया, धर्मेंद्र गेंदर उपस्थित थे.

हर 6 महीने में लाएंगे राहुल गांधी को

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नव भारत को बताया कि मध्य प्रदेश में हर छह महीने में राहुल गांधी को लाएंगे. इसके लिए जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन आदिवासी जिलों में झाबुआ, डिंडोरी,बड़वानी में भी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर युवाओं से राहुल गांधी की बातचीत का विचार किया जा रहा है. आगे की रुपरेखा बनने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी.

शहर के बिजली उपभोक्ताओं को 9 करोड़ रुपए टीओडी छूट

इंदौर. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र मालवा निमाड़ में अब तक सोलह लाख साठ हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके हैं. ये स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर पावर फैक्टर छूट और सौर ऊर्जा अवधि सुबह 9 से शाम 5 तक विद्युत खपत पर टाईम आफ द डे (टीओडी) छूट दिलाने में कारगर साबित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर इंदौर, उज्जैन, रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं. इन स्मार्ट मीटरों से शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा टीओडी छूट का फायदा मिल रहा है. इंदौर शहर के 6.13 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एक माह में करीब नौ करोड़ रुपए की टीओडी रियायत दी गई. उज्जैन जिले के 1.23 लाख उपभोक्ता को 1.66 करोड़ रुपए की टीओडी रियायत दी गई.

कर्मचारी हित के मुद्दों पर हुई चर्चा, सदस्यों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी साख संस्था की 38वीं वार्षिक सभा संपन्न

नवभारत न्यूज़

इंदौर. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था के अंशधारी सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा रविवार को संपन्न हुई. सभा में संस्था के कार्यों, कर्मचारी हित से जुड़े विषयों और सहकारिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

सभा में संस्था के अध्यक्ष राकेश सिलावट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सियावती लोनारे, सचिव कमल सेन अहिरवार, कोषाध्यक्ष संजय नथानियल, सह-सचिव महेश श्रीवास सहित संचालक मंडल के सदस्य एवं बड़ी संख्या में अंशधारी सदस्य उपस्थित रहे. शिक्षक संघ की ओर से गंगाराम वास्केल ने भी सहभागिता की.

इस दौरान चैन सिंह यादव और वीरेंद्र जोशी ने संस्था एवं कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए. पदाधिकारियों ने सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के सहयोग और सहभागिता के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सदस्यों के विश्वास, सुझाव और सहयोग से संस्था की 38वीं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

विशेषज्ञों ने इंजीनियरिंग में गणित, एआई और आईटी की उपयोगिता बताई

आईईटी में एप्लाइड साइंस पर राष्ट्रीय सेमिनार

नवभारत न्यूज़

इंदौर. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग की ओर से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त विज्ञान भविष्य की रूपरेखा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया.

भारत के लिए अभियांत्रिकी थीम पर हुए सेमिनार में विशेषज्ञों ने आधुनिक इंजीनियरिंग, तकनीकी नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में एप्लाइड साइंस की भूमिका पर चर्चा की. अतिथि विशेषज्ञ प्रो. श्रेणिक बंडी ने इंजीनियरिंग में गणित की उपयोगिता को उदाहरणों के साथ समझाया. डॉ. दिलीप वागेला ने औद्योगिक प्रदूषण के मापन और समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की जानकारी दी. सेमिनार में शोधार्थियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सहभागिता की. आयोजन संस्थान के निदेशक प्रो. प्रतोष बंसल के मार्गदर्शन में प्रो. शशि प्रकाश, डॉ. सूफिया अज़ीज़ एवं विभागीय स्टाफ ने किया. आभार प्रो. डॉ. धीरज मंडलोई ने माना.

एक नजर में

व्यापारियों ने उठाए सवाल, शुल्क और रिफंड की व्यवस्था हो स्पष्ट

यूपीआई भुगतान पर एमडीआर की नई चिंता, रिफंड हुआ तो शुल्क कौन लौटाएगा?

नवभारत न्यूज़

इंदौर. 2 हजार से अधिक के पात्र यूपीआई मर्चेंट लेन-देन पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को लेकर व्यापारियों की चिंता अब केवल शुल्क तक सीमित नहीं है. व्यापारियों ने रिफंड की स्थिति में कटे हुए एमडीआर के समायोजन को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

उनका कहना है कि बिक्री के समय शुल्क कटने के बाद यदि ग्राहक सामान वापस कर देता है तो व्यापारी को पूरी राशि लौटानी होगी. ऐसे में कटे हुए एमडीआर की वापसी या समायोजन किस तरह होगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था जरूरी है. इंदौर मारोठिया बाजार व्यापारी संघ के सचिव अंकुश जैन और क्लाथ मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के मंत्री कैलाश मूंगड अक्षय जैन ने कहा कि कम मार्जिन वाले कारोबार में 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त लागत भी महत्वपूर्ण है. अक्षय जैन ने कहा कि 20 हजार की बिक्री पर एमडीआर कटने के बाद पूरा माल वापस होने पर व्यापारी को ग्राहक को पूरी 20 हजार रुपए की राशि लौटानी होगी. ऐसे में पहले कटे अक्षय जैन का स्वत: रिफंड होगा या इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए. व्यापारियों ने आंशिक रिफंड, ऑर्डर कैंसिलेशन और विवादित भुगतान की स्थिति में भी शुल्क के स्वत: एवं पारदर्शी समायोजन की मांग की है. अंकुश जैन ने कहा कि कपड़ा बाजार में प्रतिस्पर्धा के चलते हर अतिरिक्त लागत ग्राहक पर डालना संभव नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर 23 सितंबर को प्रस्तावित 'नो यूपीआई डे' को व्यापारियों ने विरोध के साथ-साथ डिजिटल भुगतान पर बाजार की निर्भरता समझने का माध्यम बताया है.

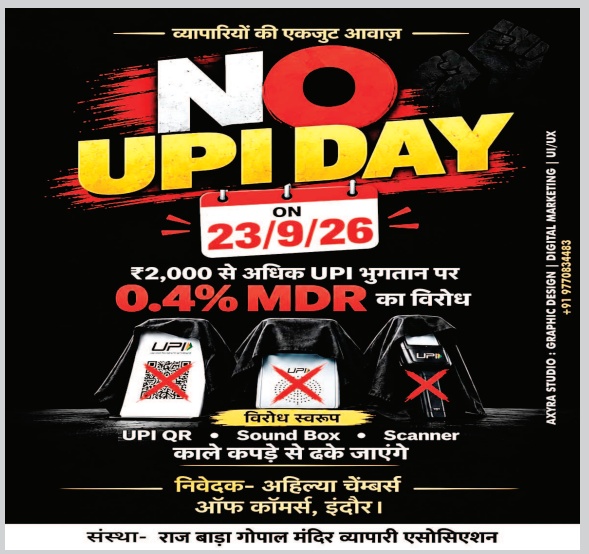

अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त सचिव एवं इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के अनुसार इस दिन यूपीआई, नकद और कार्ड से हुए भुगतान तथा कुल बिक्री के आंकड़ों की सामान्य दिन से तुलना की जाएगी. इससे कारोबार में यूपीआई की वास्तविक हिस्सेदारी का आकलन किया जा सकेगा.

व्यापारियों का कहना है कि वे डिजिटल भुगतान के विरोध में नहीं हैं. उनकी मांग केवल इतनी है कि प्रस्तावित एमडीआर की लागत और रिफंड की स्थिति में शुल्क समायोजन की व्यवस्था स्पष्ट, पारदर्शी और स्वचालित हो. सरकार के अनुसार संख्या के आधार पर करीब 96 प्रतिशत पी2एम यूपीआई लेन-देन प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे.